तिब्बत देश

लियू शियाओबो के नोबेल पुरस्कार से भयभीत चीन

चीन सरकार ने चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता लियू शियाओबो को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर जैसी गुस्से और बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है ठीक वैसी ही घबराहट सोवियत संघ के एलेक्सांद्र सोल्ज़ेनित्सिन और आंद्रेई सखारोव तथा पोलैंड के लेख वालेज़ा को नोबेल दिए जाने पर मास्को और अन्य कम्युनिस्ट सरकारों ने व्यक्त की थी।

तब भी भारत समेत दुनिया भर के कम्युनिस्ट समर्थकों ने नोबेल कमेटी को एक 'कम्युनिज्म विरोधी गिरोह' बताया था और नोबेल पुरस्कार को कम्युनिस्ट देशों को तोड़ने वाला 'षडयंत्र' बताकर इन पुरस्कारों के महत्व को कम करने की कोशिश की थी। बाद में इन देशों से कम्युनिज्म का जनाज़ा उठने पर दुनिया को समझ में आया कि सोल्ज़ेनित्सिन, सखारोव, वेक्लाव हावेल और लेख वालेज़ा जैसे साहसी लोग कम्युनिस्ट व्यवस्था के अमानवीय चरित्र को बेनकाब करने वाले ईमानदार आइने थे और कम्युनिस्ट शासन उनकी आलोचना की वजह से नहीं बल्कि अपने जनता विरोधी पापों के वज़न से ध्वस्त हुआ।

54 वर्षीय लियू शियाओबो एक चर्चित चीनी साहित्यिक आलोचक हैं और पिछले लगभग 20 साल से चीन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र समर्थक भूमिगत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 1989 में युवाओं के लोकतंत्र विरोधी 'तिएनअनमन चौक प्रदर्शनों' में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण वह हमेशा से चीन सरकार की काली सूची में रहे हैं। दिसंबर 2008 में उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली की मांग करने वाली घोषणा 'चार्टर–08' तैयार किया जो काफी हद तक चार्टर–77 जैसी है जिसे 1977 में तत्कालीन कम्युनिस्ट चैकोस्लोवाकिया में वेक्लाव हावेल के नेतृत्व वाले भूमिगत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तैयार किया था। इस चार्टर ने कम्युनिस्ट सरकारों के अमानवीय जनविरोधी चरित्र को जगजाहिर करने में बडी भूमिका निभाई।

चार्टर–08 को 8 दिसंबर 2008 के दिन संयुक्त राष्ट्र मानविधकार घोषणा की 60 सालगिरह की पूर्व संध्या पर जारी किया जाना था। उस पर 303 चीनी बुद्धिजीवियों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे। लेकिन इसे जारी करने से केवल दो घंटे पहले ही लियू को चीनी खुफिया पुलिस पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। इस चार्टर में कानून पर आधारित शासन, एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के बजाए बहुदलीय लोकतंत्र, बोलने की आजादी और सभाएं करने की आजादी जैसे मूल मानवाधिकारों वाली मांगें शामिल हैं। बाद में 23 जून 2009 को लियू को पूरी तरह गिरफ्तार कर लिया गया। 25 दिसंबर के दिन केवल दो घंटे के मुकदमे के बाद उन्हें चार्टर–08 के माध्यम से सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने और सरकार की सत्ता को चुनौती देने के लिए 'देशद्रोही' मानते हुए 11 साल की सजा सुना दी गई। तब से वह बीजिंग की एक जेल में बंद हैं। इस बीच चीन के लगभग दस हजार लोकतंत्रवादी भूमिगत समर्थक इंटरनेट के माध्यम से इस चार्टर पर अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं।

पिछले दिनों लियू शियाओबो को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर चीन सरकार की प्रतिक्रया देखने सुनने लायक थी। बीजिंग के विदेश मंत्रालय और अधिकांश सरकारी मुखपत्रों ने नोबेल कमेटी के इस फैसले को एक 'अपराधी' को सम्मानित करने की 'बेहूदा हरकत' बताकर चीन सरकार की बेचारगी का पहला संकेत दिया। सरकारी प्रवक्ता की गुस्से भरी टिप्पणी थी, ''चीन सरकार को यह सवाल पूछने का अधिकार है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार को इतना बेहूदा बना दिया गया है कि इसे एक चीन विरोधी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा लगता है कि नोबेल कमेटी चीन में शांति और एकता देखने के बजाए उसे वैचारिक टकराव के आधार पर टूटा हुआ देखना चाहती है, बल्कि बेहतर शब्दों में कहा जाए तो वह चीन को सोवियत संघ की तरह तोड़ना चाहती है।''

एक ओर चीन सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला मीडिया लियू और नोबेल कमेटी के खिलाफ विदेशों में ज़हर उगल रहा था पर दूसरी ओर पहले 48 घंटे तक चीन की जनता को इसकी भनक भी नहीं मिलने दी गई कि एक चीनी नागरिक को यह पुरस्कार मिला है। लियू के बारे में सरकारी मीडिया पर केवल यही बताया जाता रहा है वह एक 'अपराधी' है जो 'देशद्रोह' के कारण जेल में बंद है। यहां तक कि लियू की फोटोग्राफर पत्नी लियू शिया को भी जेल में उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है ताकि वह विदेशी पत्रकारों या राजदूतों से न मिल पाएं। पुलिस ने विदेशी राजदूतों को भी जेल में लियू से नहीं मिलने दिया गया।

गुआंगझू (कैंटन) जैसे शहरों में जहां चीनी नागरिक हांगकांग और दूसरे विदेशी टीवी देख सकते हैं, वहां दो दिन तक अधिकांश विदेशी टीवी सिग्नल जाम कर दिए गए। गुआंगझू में हांगकांग केबल टीवी के 30 मिनट के समाचार बुलेटिन में से लियू के नोबेल पुरस्कार से जुड़े 20 मिनट के हिस्से को ब्लॉक करके उसकी जगह चीन सरकार के 'लोकमहत्व' वाले प्रसारण दिखाए गए। इनमें से एक शिक्षा विज्ञापन का विषय था ''खाना खाने से पहले हाथ धोने जरूरी हैं''। चीन समर्थक फीनिक्स टीवी में भी टिकर पर सरकारी सैंसर ने एक तिहाई मोटी पीली पट्टी चढ़ाने के बाद ही प्रसारण होने दिया।

आखिरकार नोबेल घोषणा के 48 घंटे बाद लियू की पत्नी को अपने पति से जेल में मिलने और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने का समाचार देने की इजाजत दी गई। खबर सुनने के बाद प्रसन्न लियू ने इस पुरस्कार को ''तिएनअनमन चौक आंदोलन के शहीदों की आत्माओं'' को समर्पित किया। आम चीनी नागरिकों को जब यह समाचार मिला तो वे बेचारे इसी सवाल से परेशान रहे कि आखिर ऐसा कौन चीनी नागरिक है जिसे वे तो नहीं जानते पर जिसे पूरी दुनिया ने सम्मानित करने का फैसला किया है। सरकारी अखबारों और इंटरनेट पर जारी नागरिकों की टिप्पणियों में नोबेल कमेटी की इस बात के लिए जमकर आलोचना हो रही है कि उसने एक 'अपराधी' और 'देशद्रोही' को सम्मानित करने का घटिया फैसला किया।

लेकिन लियू को नोबेल की घोषणा ने चीन के ऐसे सब वर्गों में उत्साह भर दिया है जो पिछले कई दशक से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का फासीवादी जुआ उतारने को उत्सुक हैं। इनमें लोकतंत्रवाद और मानवाधिकारवादी आंदोलन के लोग हैं; फालुन गांग और हुई (मुस्लिम) और ईसाई मत में विश्वास के कारण आतंक और दमन में जीने वाल समाज हैं; मंचूरिया, पूर्वी तुर्किस्तान (शिंजियांग) भीतरी मंगोलिया और तिब्बत जैसे वे दर्जनों देश हैं जिन पर हान चीनियों ने पिछले कुछ दशक से गैरकानूनी और जबरन कब्जा जमाया हुआ है और; वे करोड़ों चीनी किसान और ग्रामीण हैं जिन्हें 'आर्थिक विकास' के नाम पर उनकी जमीनों और घरों से नाममात्र के मुआवज़े के बूते पर उजाड़ा जा चुका है।

इस घोषणा से ठीक पहले चीनी प्रधानमंत्री वेन जिया बाओ ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने लोकतंत्र बहाली की ठीक वही मांगें रखी थीं जो लियू के चार्टर–08 का आधार हैं। नोबेल घोषणा के तुरंत बाद हजारों चीनी बुद्धिजीवियों ने चार्टर–08 पर हस्ताक्षर करके दिखा दिया है कि चीन में हवा किधर बह रही है। और सबसे हैरानी की बात तो यह हुई कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई पुराने नेताओं ने भी संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके देश में अधिक आजादी की मांग उठा दी है।

चीन में ये सारे संकेत ठीक वैसे हैं जैसे सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के टूटने से ठीक पहले दिखाई देने लगे थे। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को चुनना है कि वे चीन को शांतिपूर्वक एक लोकतांत्रिक देश बनने देने के पक्ष में है या फिर तानाशाही से चिपके रहकर सोवियत संघ की तर्ज पर चीन को फिर से मूल 56 देशों में बंटने देना चाहेंगे?

— विजय क्रान्ति

टोयोटा–एनएएससीएआर पेंट स्कीम प्रतियोगिता में पहुंची 'फ्री टिबेट' कार

(फायुल , 5 अगस्त)

टोयोटा के द्वारा आयोजित की जा रही एनएएससीएआर पेंट स्कीम प्रतियोगिता में एक ''फ्री टिबेट'' (तिब्बत को आज़ाद करो) नारे वाली रेस कार भी पहुंची है। इस डिजाइन को अमेरिका के अलास्का से कार्ल जोंस ने इस प्रतियोगिता में दाखिल कराया है, और इसे प्रतियोगिता के ''कॉज'' श्रेणी में दाखिला मिला है। जोंस तिब्बत की मुक्ति के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। उन्होंने फायुल डॉट कॉम से कहा कि उन्हें लगा कि यह प्रतियोगिता तिब्बत की आवाज को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और इसे तिब्बत की मुक्ति के लिए रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यही सोच कर उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी कंप्यूटर के सहारे डिजाइन तैयार करते हैं। अगर इस डिजाइन को अधिक वोट मिलता है और यह कॉज श्रेणी की तरफ से टॉप टेन की सूची में शामिल होता है तो यह फाइनल में पहुंच जाएगा।

इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक वोट हासिल कर विजेता बनने वाले डिजाइन पर टोयोटा एक रेस कार बनाएगा, जिसका इसी साल बाद में फिनिक्स, अरिजोना में पूरे एक सप्ताह के लिए डिस्प्ले रेस किया जाएगा। जोंस ने कहा कि यह एक बेहतरीन विचार है, इससे वैसे हजारों लोग भी तिब्बत की मुक्ति अभियान के बारे में जानेंगे, जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा।

इस प्रतियोगिता में कुल दस श्रेणी हैं और हर श्रेणी से दस सबसे अच्छी डिजाइन का चुनाव किया जाएगा। और इस तरह प्रतियोगिता के फाइनल में इन 100 कारों में सबसे अधिक वोट पाने की प्रतियोगिता होगी। जोन ने आशा जताते हुए कहा कि अगर यह डिजाइन प्रतियोगिता जीतने में सफल होती है तो तिब्बत मुक्ति का संदेश टेलीविजन देखने वाले हजारों दर्शकों तक पहुंचेगा और इसके साथ ही कुछ बहस भी शुरू होने की संभावना है।

पाकिस्तान ने कहा है कि वहां आए अभूतपूर्व बाढ़ से 1.4 से 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप नुकसान हुआ है जिससे वहां मानवता के लिए अब तक की सबसे गंभीर त्रासदी आ खड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इस भीषण बाढ़ में करीब 1,600 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पाकिस्तान सरकार ने 1,300 लोगों के मरने की पुष्टि की है।

दलाई लामा ने बढ़ते बाढ़ की घटनाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग पर चेताया

(एएनआई, 14 अगस्त, धर्मशाला)

दलाई लामा ने कहा है कि समूचे एशिया आने वाले विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के लिए ग्लोबल वार्मिंग को वजह माना जा सकता है। उन्होंने इन विनाशकारी घटनाओं से पीड़ित लोगों के लिए शनिवार को प्रार्थना की। बौद्ध आध्यात्मिक नेता ने कहा कि पाकिस्तान, भारत और चीन में हुई जन–धन की भारी हानि से उन्हें गहरा दुःख हुआ है और उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह विनाश ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ हो सकता है। उन्होंने रूस की हालत पर भी चिंता जाहिर की जो जंगलों में अब तक की सबसे बड़ी आग का सामना कर रहा है। उत्तर भारत के धर्मशाला स्थित अपने आवास से जारी बयान में दलाई लामा ने कहा, 'विशेषज्ञों का कहना है ये बाढ़ काफी असामान्य तरह के हैं और रूस में जो विनाशकारी आग लगी है वह ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरण विनाश काफी बढ़ जाने से पैदा हुए घबरा देने वाले लक्षण हैं।

दलाई लामा ने कहा, 'अपने साझा और नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के उपायों पर विचार के लिए परस्पर सामंजस्य से अंतरराष्ट्रीय प्रयास करना चाहिए।" पाकिस्तान ने कहा है कि वहां आए अभूतपूर्व बाढ़ से 1.4 से 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप नुकसान हुआ है जिससे वहां मानवता के लिए अब तक की सबसे गंभीर त्रासदी आ खड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इस भीषण बाढ़ में करीब 1,600 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पाकिस्तान सरकार ने 1,300 लोगों के मरने की पुष्टि की है। चीन भी भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और वहां आए बड़े भूस्खलन की घटना से करीब 1,150 लोगों की मौत हो गई है। भारत में भी करीब एक सप्ताह पहले अचानक हुई तूफानी बारिश से हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में भारी बाढ़ आ गई जिसमें करीब 189 लोग मारे गए, जबकि 400 अन्य लोग गायब हैं।

अमेरिकी सरकार ने तिब्बत पर संवेदनशील बातचीत का समर्थन किया

(टिबेट डॉट नेट, 27 अगस्त, धर्मशाला)

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस को दी तिब्बत वार्ताओं पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का समर्थन किया है कि लंबे समय से चल रहे मसले को हल करने के लिए परमपावन दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों और चीन सरकार के बीच पर्याप्त वार्ता होनी चाहिए। 'यूएस पॉलिसी ऑन टिबेट' नाम की साल 2009–10 की इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य को इस बात के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया गया है कि वह

दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू कर तिब्बत पर किसी समझौते का रास्ता निकाले। इसमें चीन और दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच अब तक हुई वार्ताओं की स्थिति की भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'अमेरिकी सरकार का मानना है कि तिब्बती क्षेत्रों में लगातार जारी तनाव से निपटने में चीन को जिन कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उससे बचने के लिए दलाई लामा एक रचनात्मक साझेदार साबित हो सकते हैं। उनके विचारों को तिब्बती समुदाय में व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता हे और उन्हें तिब्बतियों के बड़े बहुमत का विश्वास हासिल है। एक अंतिम समाधान निकालने के लिए वह लगातार अहिंसा की वकालत करते रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "तिब्बती लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके लिए चीन का दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से संपर्क चीनी सरकार और तिब्बती जनता दोनों के हित में है। इन समस्याओं का समाधान यदि नहीं निकल पाया तो चीन के भीतर तनाव बढ़ जाएगा जो चीन के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा।" अमेरिकी सरकार ने एक बार फिर चीन से यह आह्वान किया है कि वह तिब्बती जनता के विशिष्ट धर्म, भाषा, सांस्कृतिक विरासत और उनके मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान करे।

अमेरिकी सरकार ने एक बार फिर चीन से यह आह्वान किया है कि वह तिब्बती जनता के विशिष्ट धर्म, भाषा,सांस्कृतिक विरासत और उनके मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान करे।

चीन ने दलाई लामा और मनमोहन सिंह के मुलाकात पर आपत्ति की

(एएफपी, 24 अगस्त, बीजिंग)

हाल में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात का विरोध करते हुए चीन ने भारत सरकार को चेताया कि वह अब तक बने सभी तरह के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश न करे। जबकि निर्वासित बौद्ध भिक्षु के कार्यालय ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में मनमोहन सिंह से नई दिल्ली में हुई मुलाकात एक अनौपचारिक मुलाकात ही थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग यू ने अपने बयान में कहा है, "चीन किसी भी विदेशी राजनीतिक नेता के दलाई लामा से मिलने के खिलाफ है। हमने अपना यह रुख भारत को भी बता दिया है। भारतीय सरकार ने कई बार यह कहा है कि तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और वे तिब्बती नागरिकों को चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं देंगे। चीन को उम्मीद है कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम रहेगी, तिब्बत से जुड़े मसलों को सावधानी से देखेगी और चीन–भारत संबंधों को बिगाड़ने से बचेगी। दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी की जगह बार–बार यह कहते रहे हैं कि वे सिर्फ स्वायत्तता चाहते हैं, लेकिन चीन की तरफ से यह मांग बढ़ती जा रही है कि दुनिया के नेता दलाई लामा से मुलाकात न करें। चीन द्वारा दलाई लामा के देश पर कब्जे के बाद वहां एक जनक्रांति हुई जिसके बाद करीब 50 साल पहले दलाई लामा भारत आ गए। तबसे वह पर्वतीय शहर धर्मशाला निर्वासित सरकार चला रहे हैं। चीन ने पहले यह भी आरोप लगाया है कि दलाई लामा भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ाना चाहते हैं। पिछले साल जब दलाई लामा ने भारत के एक हिमालयी राज्य की यात्रा की थी तो चीन आगबबूला हो गया था, उसने कहा था कि यह भारत–चीन संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश है।

चीन से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या ने तिब्बतियों की जीविका को खतरे में डाला

(टिबेट डॉट नेट 6 अगस्त, धर्मशाला)

बड़ी संख्या में चीनी मूल के लोगों के तिब्बत में आकर बसने के कारण यहां तिब्बतियों के सामने जीवनयापन की समस्या पैदा हो गई है। तिब्बतियों की जीविका छिन गई है। चीन से आए लोगों में अधिकतर अपराधी हैं और इन लोगों के कारण तिब्बती जीवन मूल्य और संस्कृति को नुकसान हो रहा है। यह जानकारी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट से मिली है।

तिब्बत को 2006 में रेलमार्ग से जोड़े जाने के कारण और चीन के द्वारा यहां चलाई गई अनेक विकास परियोजनाओं के कारण चीनी लोगों के तिब्बत आकर बसने की गति में काफी तेजी आ गई है। उधर 2008 में तिब्बतियों के द्वारा किए गए शांतिपूर्ण विरोध के कारण तिब्बतियों को कई मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। उन्हें फुलटाइम और पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहे हैं। चीन सरकार ने तिब्बतियों को शहरों से इस आरोप के साथ उनके गांव की ओर खदेड़ दिया है कि वे यहां बगैर स्थाई निवास प्रमाणपत्र के रह रहे हैं।

चीनी लोगों के तिब्बत में आकर बसने और अपराध और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने को रोकने का कोई कानूनी उपाय नहीं है। उलटे तिब्बतियों

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात का विरोध करते हुए चीन ने भारत सरकार को चेताया कि वह अब तक बने सभी तरह के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश न करे।

को ही दमन और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बतियों की जीविका के खतरे में पड़ने और चीनियों के द्वारा आपराधिक गतिविधि अंजाम दिए जाने की बात एक सर्वे से भी साबित हो जाती हैं। इस सर्वे को इस साल जून में चामदो में सावा जोगांग काउंटी में संपन्न किया गया था।

सर्वे के अनुसार तिब्बत में चीनियों के द्वारा 249 दुकान ओर 52 रेस्त्रां चलाए जा रहे हैं, जबकि तिब्बतियों के द्वारा सिर्फ 53 दुकान और 30 रेस्त्रां चलाए जा रहे हैं। यहां अभी 5 वेश्यालय चीनियों के द्वारा, 11 जुए के अड्डे चीनियों के द्वारा और 3 नाइट क्लब तिब्बतियों के द्वारा चलाए जा रहे है। वेश्यावृत्ति और जुए में हो रही बढ़ोतरी के कारण जहां जानलेवा रोग बढ़ रहे हैं, वहीं युवा वर्ग में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। दूसरी ओर तिब्बत के सांस्कृतिक, पारिवारिक तानेबाने को भी खतरा पहुंच रहा है। नाइट क्लब और बार की संख्या में हो रही तेज बढ़ोतरी के कारण तिब्बत की सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक मूल्य छिन्न–भिन्न हो रहा है। इस साल सरकार ने तिब्बत में करीब 60 स्वयंसेवक पुलिस को 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया था, जो यहां चीनियों के द्वारा चलाए जा रहे बार पर नजर रख रहे थे। ये चीनी मुख्यतः सिचुआन प्रांत के है। 30 जुलाई को ल्हासा के एक अखबार में छपी एक खबर के अनुसार एक छापे के दौरान चीनियो के द्वारा चलाए जा रहे दो बार में कुल करीब 28 अपराधियों को पकड़ा गया था।

इसी तरह ल्हासा इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने 18 दिसंबर 2010 को चीनी मूल के कुछ अपराधियों को भी अपराधी ठहराया था, जिससे चीनियों के तिब्बत में आकर डेरा जमाने से तिब्बत की सामाजिक जीवन पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव और असामाजिक गतिविधियों में हो रही बढ़ोतरी की बात प्रमुखता से उजागर होती है।

चीनी वायु सेना के महत्वपूर्ण दस्तावेजों से लैस ट्रेन गंतव्य तक पहुंचा

(टिबेटन रिव्यू डॉटनेट, अगस्त 06, 2010)

चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एयर फोर्स के महत्वपूर्ण कॉम्बैट रेडिनेस मैटेरियल्स से लदा एक ट्रेन क्विंघाई–तिब्बत रेलवे होते हुए सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मुखपत्र पीपुल्स डेली में प्रकाशित खबर का हवाला देकर यह खबर छापी गई है।

श्रीलंका के गार्जियन के वेबसाइट पर इस बारे 5 अगस्त को छपी खबर में कहा गया है, ''पीएलए एयरफोर्स के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नेताओं के अनुसार उनके मिलिट्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्विंघाई–तिब्बत रेलवे के शुरू होने के बाद पहली बार रेलवे से कॉम्बेट रेडिनेस मैटेरियल तिब्बत भेजा है। यह कॉम्बैट सपोर्ट में मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन क्षमता का एक नया विकास है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महत्वपूर्ण कॉम्बैट रेडिनेस मैटेरियल की सुरक्षा के लिए पीएलए एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और जवान क्विंघाई–तिब्बत रेलवे के हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही तुरंत ट्रेन की जांच करते हैं। वे बीच–बीच में कुछ दूरी तय करने के बाद अपने अनुभवों पर विचार–विमर्श भी करते रहते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह कदम भारतीय बॉर्डर पर मुकाबले में बढ़त बनाने के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौज लंबे समय से तिब्बत के दक्षिणी हिस्से यानी अरुणाचल प्रदेश में चीनी बॉर्डर के उस पार तैनात पीएलए के खिलापफ भारतीय सेना के जवान वार ऑफ एट्रीसन छेड़े हुए हैं, जिन्हें भौगोलिक लाभ और बेहतर परिवहन सुविधा मिली हुई है। हालांकि रिपोर्ट में संदेह जताया गया है कि चीन की बढ़ती ताकत और महत्वपूर्ण कॉम्बैट रेडिनेस मैटेरियल की बेहतर परिवहन क्षमता के कारण भारत के लिए चीन के खिलाफ वार ऑफ एट्रीशन जारी रखना संभव नहीं रह जाएगा।

वेबसाइट पर प्रकाशित यह ब्लॉग बी रमन ने लिखी है, जो भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त कैबिनेट सचिव रह चुके हैं और फिलहाल चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल स्टडीज के डायरेक्टर और चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडी के एसोसिएट हैं। उन्होंने लिखा है कि चीन तिब्बत में अधिक से अधिक एयरपोर्ट बनाने की नीति पर चल रहा है, जो नागरिक और युद्धक दोनों ही कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही वह तिब्बत की रेलवे लाइन के माल ढोने की क्षमता का भी विस्तार कर रहा है। उन्होंने एक अपुष्ट रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि चीन जल्द ही तिब्बत रेलव लाइन का दोहरी करण करने वाला है, ताकि एक लाइन को पूरी तरह से माल ढोने के लिए समर्पित किया जा सके।

चीनी बांध के विरोध में भारत अरुणाचल में बनाएगा बांध

महत्वपूर्ण कॉम्बैट रेडिनेस मैटेरियल की सुरक्षा के लिए पीएलए एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और जवान क्विंघाई–तिब्बत रेलवे के हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही तुरंत ट्रेन की जांच करते हैं। वे बीच–बीच में कुछ दूरी तय करने के बाद अपने अनुभवों पर विचार–विमर्श भी करते रहते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह कदम भारतीय बॉर्डर पर मुकाबले में बढ़त बनाने के लिए उठाया गया है।

(दि इकनॉमिक टाइम्स, 6 अगस्त, 2010)

नई दिल्ली : भारत अरुणाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजना का निर्माण तेज करेगा। ऐसा वह इस क्षेत्र में हो रहे चीनी निर्माण के प्रतिरोध मे करेगा। चीन तिब्बत के यारलंग सांगपो में एक जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। हालांकि बीजिंग ने भरोसा दिलाया है कि चीन की परियोजना से भारत में नदी की प्रवाह में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन भारत फिर भी हाथ पर हाथ धर कर बैठना नहीं चाहता है। भारत सियांग नदी पर निर्माण करने के बारे में सोच रहा है। यारलंग सांगपो जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहां वह सियांग कहलाती है। इस कारण सियांग बेसिन एक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक क्षेत्र बन गया है। सियांग बेसिन का विकास करने से भारत को चीन के मुकाबले कुछ रणनीतिक बढ़त मिलेगी। अब तक भारत सुबासरी और दिबांग बेसिन पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इसके इसी महत्व को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री से वादा किया है कि वह जल्दी ही सियांग नदी बेसिन परियोजना को एनवॉयरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस जारी कर देगा। पहले कदम के तौर पर इसने पहले ही निचले सियांग में जेपी समूह की 2,700 मेगावाट परियोजना के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस निश्चित कर दिया है। अब डेवलपर को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का एक मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करना होगा।

सियांग बेसिन में लगभग 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावित क्षमता है जिसमें अब तक 11,000 मेगावाट की कुल तीन परियोजनाओं की ही पहचान की गई है। और ये तीनों अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने ऊर्जा मंत्रालय को लिखा है कि वह इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व को देखते हुए जल्द ही इन्हें अपनी ओर से स्वीकृति दे देगा।

सरकार इन परियोजनाओं के निर्बाध पूरा होने के लिए जहां परियोजना से प्रभावित होने वालों के स्थानांतरण के लिए आकर्षक पैकेज देने पर विचार कर रही है वहीं अरुणाचल सरकार को भी बेहतर इंसेटिव देने पर विचार कर रही है। चूंकि चीन की सीमा में हो रहे निरंतर विकास कार्य के मुकाबले ये परियोजनाएं भारत को मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकती है इसलिए ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित एक मंत्रिमंडलीय समूह में भी इस पर विचार किया जा रहा है। चूंकि भारत और चीन के बीच कोई जल समझौता नहीं हुआ है इसलिए अगर भारत का निचला तटवर्ती अधिकार प्रभावित होता है तो भारत चीन के सामने इस मुद्दे को उठा नहीं पाएगा। इस परिस्थिति में सियांग बेसिन का विकास भारतीय हित की रक्षा सुनिश्चित करेगा।

बुनियादी मूल्यों में चीन से आगे है भारत

(आईएएनएस, 14 अगस्त, धर्मशाला)

चीन हो सकता है कि आर्थिक रूप से भारत से आगे हो, लेकिन आज़ादी, पारदर्शिता और कानून के शासन जैसे ऐसे बुनियादी मूल्यों के मामले में वह इससे पीछे है जो कि राजनीतिक विकास के लिए जरूरी होता है। निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा ने यह बात कही है। दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं दिखते क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वह अभी कई दशक तक और जिंदा रहेंगे। चीन की आर्थिक बढ़त को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसकी तुलना भारत से की और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पिछले साल वाशिंगटन दौरे के दौरान की गई टिप्पणी को उद्धृत किया। अपने आवास पर आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहा, 'जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है चीन भारत से आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा उन्नत हो सकता है, लेकिन वह कई बुनियादी मूल्यों के मामले में भारत से पीछे है जैसे कानून का शासन, पारदर्शिता, व्यक्तिगत आज़ादी, प्रेस की आज़ादी आदि।" उन्होंने कहा, "अमेरिका और आज़ाद देश के लोग इन बुनियादी मूल्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं और वे उनका पालन करते हैं। व्यक्तिगत आज़ादी नव प्रवर्तन को बढ़ावा देती है।"

यह इंटरव्यू दलाई लामा के सरकारी बंगले में लिया गया जो 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, इसके एक तरफ हरी–भरी कांगड़ा घाटी दिखती है जिसके चारों ओर प्री–हिमालय धौलाधर पर्वत श्रेणी दिखती है।

दलाई लामा ने कहा कि हाल के दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़त बाहर के पैसे से हुआ और वहां सस्ते में मौजूद श्रमिकों का शोषण किया गया है। उन्होंने कहा, 'हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि चीन से बाहर नव प्रवर्तन अब ज्यादा निकल रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वहां हर चीज नियंत्रण में है। आज़ाद दुनिया की ताकत न केवल धन पर निर्भर है, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं। चीन में केवल यह धन के बल पर हो रहा है। इसलिए अब कई चीनी

सियांग बेसिन में लगभग 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावित क्षमता है जिसमें अब तक 11,000 मेगावाट की कुल तीन परियोजनाओं की ही पहचान की गई है। और ये तीनों अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में हैं।पर्यावरण मंत्रालय ने ऊर्जा मंत्रालय को लिखा है कि वह इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व को देखते हुए जल्द ही इन्हें अपनी ओर से स्वीकृति दे देगा।

इस वजह से 'क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 22.5 लाख संख्या वाली ताकतवर जनमुक्ति सेना के जवानों को भारतीय सीमा पर ज्यादा आगे और टिके रह सकने वाली जगह पर तैनात कर दिया गया है। इन जवानों को परमाणु क्षमता वाले सीसीए–5 बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस किया गया है। 'चीन जनवादी गणराज्य से जुड़ी सैन्य और सुरक्षा गतिविधियां' विषय पर पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस क्षेत्र में हवाई सैनिकों के इस्तेमाल की भी कोई योजना बना सकता है।

बुद्धिजीवी और नेता यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह एक कमजोरी है और वे उसे बदलना चाहते हैं। वे अर्थव्यवस्था और राजनीतिक क्षेत्र, दोनों में आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। चीन में अब बदलाव की बयार बह रही है।"

दलाई लामा ने कहा कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की जगह ले चुके चीन का उभार 'सकारात्मक" विकास है, जिसकी वजह से चीन में इतना 'आत्मविश्वास" होना चाहिए कि वह तिब्बत जैसे जटिल मसलों को सुलझा सके। उन्होंने कहा, 'चीन यदि ज्यादा आत्मविश्वास हासिल करता है तो घरेलू समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझा सकता है। यदि उनकी समूची परिस्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी तो वह जटिल मसलों को उठाने में हिचकिचाएगा। इस लिहाज से चीन के ज्यादा ताकतवर होने की बात उपयोगी है। यह ज्यादा सकारात्मक बात है।" वह हाल में छपी इन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि जापान को पछाड़कर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

दलाई लामा ने कहा, 'निश्चित रूप से पिछले 60 सालों में अस्सी के दशक तक जब चीन अलग–थलग था तो जानकारी की कमी की वजह से वहां के लोगों की सोच बहुत सीमित थी। देंग जियोपिंग के अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद चीन का बाहरी दुनिया से व्यापक संपर्क बना। इसलिए अब ज्यादा चीनी नागरिक खुले दिमाग के और ज्यादा उदार सोच के हैं। चीन के बढ़ते आत्मविश्वास और खुले दिमाग की चर्चा करते हुए तिब्बती नेता ने कहा, 'उदाहरण के लिए पिछले दो सालों में हमने चीनी नागरिकों द्वारा तिब्बत पर चीनी भाषा में कई लेख देखे हैं जिनमें हमारे रवैए का काफी समर्थन किया गया है और सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है।

उन्होंने कहा, '30 से 40 साल पहले यह देखना असंभव था। लेकिन अब यह सब चीजें हो रही हैं। अपने उत्तराधिकार के सवाल पर 75 साल के आध्यात्मिक नेता ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह अभी कई दशक और जिएंगे और उत्तराधिकारी चुनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। दलाई लामा ने आईएएनएस के संवाददाता को बताया, 'साल 1969 में ही मैंने कहा था कि दलाई लामा के संस्था को बने रहना चाहिए या नहीं इसका निर्णय तिब्बती लोगों को करना है। हो सकता है कि अगले पांच साल में जब मैं 80 साल का हो जाउं तब भी यह सवाल दोहराया जाए कि इस संस्था को आगे जारी रखा जाएगा या नहीं। दलाई लामा ने कहा, 'यदि बहुमत यह कहता है कि परंपरागत रास्ता चुनना बेहतर है तो एक बार फिर मैं उसी बात को पुष्ट करूंगा जो मैं कई सालों से कहता आया हूं कि यदि पुनर्जन्म की तलाश हुई तो इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह होगा कि पिछले जन्म में जो लक्ष्य हाथ में लिया है उसे पूरा करना है। इसलिए यदि मेरी मौत यहां एक शरणार्थी के रूप में हो जाती है तो मेरे पुनर्जन्म को तार्किक रूप से मेरे अधूर कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। निश्चित रूप से चीन एक और आधिकारिक दलाई लामा का चयन करेगी। इस तरह जब दो दलाई लामा होंगे तो जटिलता और बढ़ जाएगी।"

दलाई लामा ने कहा, 'कुछ कट्टरपंथी –कम्युनिस्ट– सोचते हैं कि वे विशेषज्ञ हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है कि चीनी कम्युनिस्ट कट्टरपंथी मुझे एक शैतान के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ उन्हें एक शैतान के पुनर्जन्म को लेकर भी काफी चिंता है। दलाई लामा की संस्था को व्यापक संदर्भ में देखते हुए उन्होंने कहा, 'तिब्बती भावना दलाई लामा पर नहीं, बल्कि तिब्बती संस्कृति और लोगों पर निर्भर है। जब तक तिब्बती लोग रहेंगे, तिब्बती भावना जिंदा रहेगी। इसलिए मैं रहूं या न रहूं, तिब्बती भावना बरकरार रहेगी।" गौरतलब है कि 1959 में दलाई लामा तिब्बत से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला चले आए थे जहां निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय है।

भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से चीन सतर्कः अमेरिका

(टीएनएन, 18 अगस्त, नई दिल्ली)

मजबूत पांवों वाला ड्रैन हो सकता है दुनिया भर में तेजी से अपने पंख फैला रहा हो, लेकिन उसे अपने पड़ोसी हाथी की बढ़ती ताकत से थोड़ा सतर्क होना पड़ रहा है। अमेरिका रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन के नवीनतम आकलन के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका चीन बढ़ती सैन्य ताकत के दम पर भले ही महाबली हो चुका हो, लेकिन वह 'भारत के बढ़ते आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत के सामरिक निहितार्थों को लेकर सचेत है'। इस वजह से 'क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 22.5 लाख संख्या वाली ताकतवर जनमुक्ति सेना के जवानों को भारतीय सीमा पर ज्यादा आगे और टिके रह सकने वाली जगह पर तैनात कर दिया गया है। इन जवानों को परमाणु क्षमता वाले सीसीए–5 बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस किया गया है। 'चीन जनवादी गणराज्य से जुड़ी सैन्य और सुरक्षा गतिविधियां' विषय पर

पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस क्षेत्र में हवाई सैनिकों के इस्तेमाल की भी कोई योजना बना सकता है।

हालांकि भारत के रक्षा बलों के लिए इसमें कुछ भी चौकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे एक बात तो पुष्ट होती है कि चीन 4,057 किलोमीटर लंबी अनसुलझी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार अपने भारी सैन्य ढांचे को उन्नत बना रहा है। उदाहरण के लिए उपग्रह से मिले चित्रों ने बहुत पहले यह खुलासा कर दिया था कि मध्य चीन के एक बड़े क्षेत्र में क्विंघाई प्रांत के देलिंघा और दा क्वाइदम के निकट परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए करीब 60 लॉन्च पैड बनाए गए हैं जिनसे आसानी से उत्तर भारत को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा नया चीनी रोड मोबाइल डीएफ–31 मिसाइल 11,200 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है और जेएल–2 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल से 7,200 किलोमीटर तक वार किया जा सकता है। ये सब हथियार अमेरिका को चिंता में डालते हैं।

निश्चित रूप से चीन त्रिग पहाड़ियों से पूर्वी लद्दाख के पानगांग सो लेक, सिक्किम के फिंगर एरिया और अरुणाचल के असाफिला सेक्टर तक लगातार नियंत्रण रेखा में घुसपैठ करके भारत को परेशान करता रहा है। वास्तव में पेंटागन की रिपोर्ट कहती है, "पिछले सालों में भारत और चीन के बची राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध मजबूत होने के बावजूद 4,057 किलोमीटर सीमा पर तनाव बना हुआ है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के मामले पर जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और इसी प्रकार अक्साई चिन क्षेत्र में भी तनाव है। यह देखते हुए कि दोनों पक्षों ने साल 2009 में अपने दावों के पक्ष में कदम तेज किए थे, रिपोर्ट में उस घटना का हवाला दिया गया जब चीन ने एशियाई विकास बैंक से भारत को मिलने वाले 2.90 अरब डॉलर के कर्ज पर रोक लगा दिया क्योंकि उसका कहना था कि इस कर्ज का एक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश की जल परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है, 'पहली बार ऐसा देखा गया कि चीन ने इस विवाद में एक बहुपक्षीय संस्था के माध्यम से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। भारत और चीन के बीच सामरिक एवं सैन्य क्षमताओं के बीच भारी असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन 13 लाख संख्या वाली मजबूत भारतीय सेना को अब 1962 की कम साजोसामान वाली सेना के समान नहीं समझा जा सकता। भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए जनवरी, 2011 तक अपने सबसे महत्वाकांक्षी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि–5 का परीक्षण करना चाहता है जो 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है।

भारतीय जनरल को चीन में प्रवेश नहीं देने के कारण रक्षा समझौता पटरी से उतरा

(इंडियन एक्सप्रेस, अगस्त 27, 2010, नई दिल्ली)

चीन ने एक आक्रामक कदम उठाते हुए भारत के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल को चीन जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वे जम्मू एवं कश्मीर के एक संवेदनशील क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इसका मुखर विरोध करते हुए भारत ने भी चीनी सैन्य अधिकारियों की भारत यात्रा को तब तक के लिए रद्द कर दिया, जब तक की मुद्दा सुलझा नहीं लिया जाता है।

भारत के विदश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारी चीनी सरकार से बात चीत जारी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस साल जनवरी में हुई सलाना बैठक में जनरल स्तर के अधिकारियों का एक दूसरे देश में यात्रा करने को लेकर एक समझौता हुआ था। जुलाई के लिए यात्रा का कार्यक्रम तय था, लेकिन तब तक यह तय नहीं हुआ था कि इस यात्रा में किसे भेजा जाएगा।

चीन ने अपने कब्जे वाले कश्मीरी क्षेत्र गिलगित में 11,000 सैन्य बलों की तैनाती की

(इंडियन एक्सप्रेस, 28 अगस्त,न्यूयॉर्क)

चीन ने कब्जाए हुए कश्मीरी क्षेत्र गिलगिट और बाल्तिस्तान में 11,000 सैन्य जवानों की तैनाती कर दी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पाकिस्तानी शासन के खिलाफ विद्रोह की संभावना पैदा हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर में लिखा कि गिलगित और बाल्तिस्तान में हुए दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक तो वहां पाकिस्तानी शासन के खिलाफ बगावत का माहौल बन गया है, दूसरे वहां 7000 से 11,000 चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जवानों का जमावड़ा हो गया है।

अखबार में कहा गया है कि चीन इस क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखना चाहता है क्योंकि वह इस क्षेत्र से होकर खाड़ी देशों तक पहुंच बनाना चाहता है। इसलिए वह यहां तेजी से रेल और सड़क मार्ग बना रहा है।

'पहली बार ऐसा देखा गया कि चीन ने इस विवाद में एक बहुपक्षीय संस्था के माध्यम से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। भारत और चीन के बीच सामरिक एवं सैन्य क्षमताओं के बीच भारी असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन 13 लाख संख्या वाली मजबूत भारतीय सेना को अब 1962 की कम साजोसामान वाली सेना के समान नहीं समझा जा सकता।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1. दैवी आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा का नेतृत्व करते हुए द
2. दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ब्यालाकुप्पी के तिब्बती बस्ती में करीब 450 तिब्
   यह बैठक 26 अगस्त, 2010 को शुरू हुई।
3. लद्दाख में विनाशकारी बाढ़ की लीला को टीवी पर दिखाता एनडीटीवी चैनल।
4. टोयोटा–नैस्कार पेंट प्रतियोगिता में 'तिब्बत को आज़ाद करो' नारे वाली कार
5. परमपावन दलाई लामा पोलैंड की राजधानी वारसा शहर की मानद नागरिकता स्
6. लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल (फाइल फोटो)
7. अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताबों के लेखक सोग्याल रिनपोछे और परमपावन दलाइ
   का अवलोकन करते हुए।
8. ब्रह्मपुत्र की धारा को मोड़कर नदियों को जोड़ने की चीन की परियोजना
9. बीजिंग में रहने वाले तिब्बती लेखक वूएजर की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि
   विनाश करने वाला जो भूस्खलन हुआ था, वह ऐसा लगता है कि मानवीय गलति
10. दोरजी टाशी (फाइल फोटो)

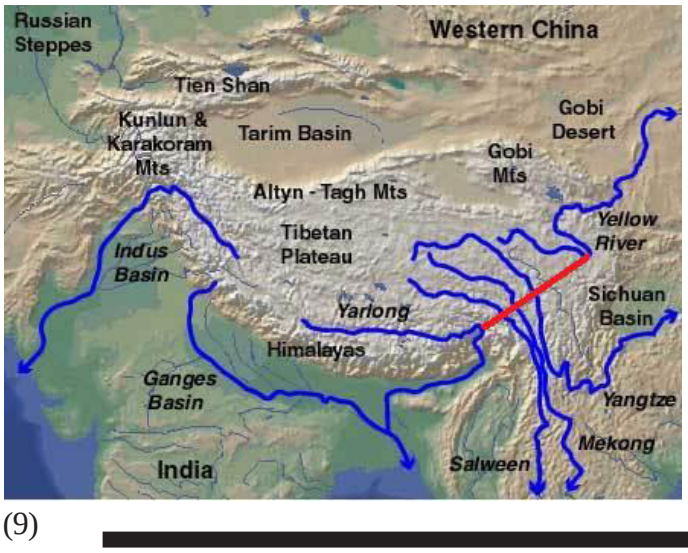

(9)

(8)

(3)

(4)

आंख से तिब्बत

हुए दलाई लामा

0 तिब्बती प्रतिनिधि पहली राष्ट्रीय आमसभा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए।

ल।

ता स्वीकार करते हुए, 29 जुलाई, 2009 (एएफपी, फाइल फोटो)

दलाई लामा के विशेष दूत लोदी ग्यारी रिनपोछे दुनिया के सबसे लंबे कैलिग्राफी स्क्रॉल

ह कि गत 8 अगस्त को तिब्बत के आमदो प्रांत (जिसे चीनी गांसू प्रांत कहते हैं) में भारी ालतियों का नतीजा था।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

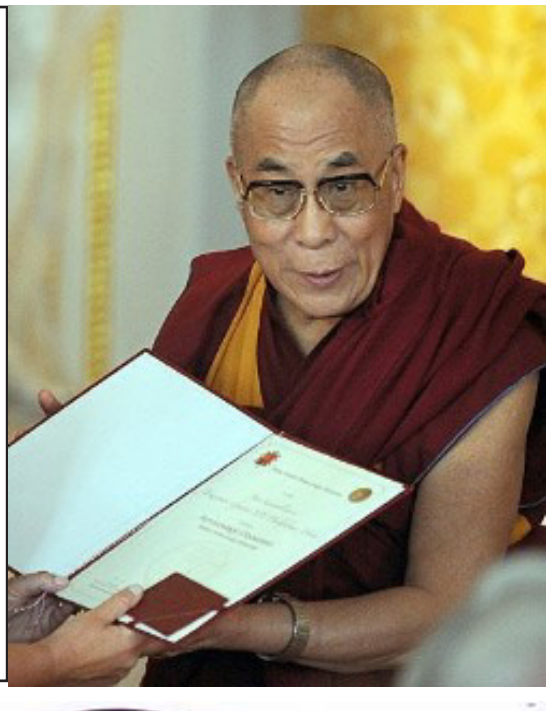

(7)

(6)

इन मार्गों से होकर चीन को अपने पूर्वी भाग से माल गाड़ियों और तेल टैंकरों को पाकिस्तान के ग्वादर और बलूचिस्तान में ओरमारा के अपने नौसैनिक कैंपों तक ले जाने में सिर्फ 48 घंटे लगेंगे। ये क्षेत्र खाड़ी के निकट हैं।

चीन पर मानवाधिकार के लिए दबाव बनाने के लिए विशेषज्ञों ने अमेरिका से अपील की

''कांग्रेसनल एक्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना'' अमेरिका के कानूनविद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का पैनल है जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इस पैनल की स्थापना एक कानून के जरिए की गई थी, जिसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश दिया गया था। इस आयोग ने 22 अक्टूबर 2009 को 'स्पेशल टॉपिक पेपर : तिब्बत 2008 –2009'नामक एक रिपोर्ट जारी किया।

(टिबेट डॉट नेट, 5 अगस्त, धर्मशाला)

मानवाधिकार और कानूनी विशेषज्ञों के एक पैनल ने अमेरिका से अपील की है कि वे चीन पर मानवाधिकार और कानून का शासन लागू करने के लिए दबाव बनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि मानवाधिकार के मोर्चे पर चीन की स्थिति बहुत खराब है और आलोचकों तथा अल्पसंख्यकों पर सख्ती बरतने के कारण चीन में मानवाधिकार की स्थिति और भी खराब हो गई है। पैनल के सदस्यों ने 3 अगस्त को ड्रिकसेन सिनेट ऑफिस भवन में चीन के मसले पर गठित कांग्रेस के कार्यकारी आयोग से इस बारे में अपनी भावनाओं से अवगत कराया। इस आयोग का नाम है : ''पॉलिटिकल प्रिजनर इन चाइना : ट्रेंड एंड इंप्लीकेशंस फॉर यूएस पॉलिसी''।

सामाचार एजेंसी रायटर ने डुई हुआ फाउंडेशन के रिसर्चर जोशुआ रोजेनविग का हवाला देते हुए लिखा है कि 2008 की शुरुआत से आमतौर पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि कानून का शासन की स्थापना की दिशा में पहले चीन में जो भी विकास हुआ था, वह या तो रुक गया है या उसकी स्थिति और भी खराब हो रही है।

उन्होंने पैनल को बताया कि इस बात के पूरे सबूत हैं कि चीन में कुछ खास अल्पसंख्यक समुदायों, सरकार के आलोचकों और अधिकारों की मांग करने वालों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जा रही है।

रोजेनविग ने बताया कि डुई हुआ फाउंडेशन चीन में राजनीतिक कैदियों को मेडिकल आधार पर जमानत देने और जल्दी रिहा करने के लिए संघर्ष कर रह है। फाउंडेशन ने 5,800 ऐसे कैदियों की सूची बनाई है, जिन्हें अहिंसक रूप से राजनीतिक और धार्मिक आवाज उठाने के लिए कैद कर लिया गया है। उधर न्यूयार्क विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ के जैरॉम कोहेन ने कहा कि जहां एक ओर चीन में कानूनी गतिविधियों में पारदर्शिता के ना होने के कारण कैदियों की सही संख्या का ठीक–ठीक पता नहीं चल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अन्य अफसोसजनक संकेत ये मिल रहे हैं कि इन कैदियों की ओर से लड़ रहे वकीलों पर भी सरकार दमनकारी कार्रवाई कर रही है। विशेषज्ञों ने पैनल से कहा कि वाशिंगटन को चीन के साथ मानवाधिकार के मसले पर साल में एक बार चलने वाली वार्ता को साल में दो बार करना चाहिए, इसमें शामिल अधिकारियों का ओहदा बढ़ाना चाहिए और स्पष्ट रूप से खास खास कैदियों से जुड़े मुद्दे उठाना चाहिए ना कि सिर्फ सैद्धांतिक बातचीत करना चाहिए जैसा कि चीन चाहता है।

पैनल में शामिल अन्य सदस्यों में थे वान यानहाई और सोफी रिचर्ड्सन। वायन यानहाई बीजिंग ऐजिक्सिंग इंस्टीट्यूअ के डायरेक्टर हैं। यह संस्था एचआईवी/एड्स, मानवाधिकार और चीन में सिविल सोसाइटी के मुद्दे पर काम करती है। सोफी रिचर्ड्सन ह्यूमैन राइट वाच की एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर हैं।

''कांग्रेसनल एक्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना'' अमेरिका के कानूनविद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का पैनल है जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इस पैनल की स्थापना एक कानून के जरिए की गई थी, जिसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश दिया गया था। इस आयोग ने 22 अक्टूबर 2009 को 'स्पेशल टॉपिक पेपर : तिब्बत 2008–2009' नामक एक रिपोर्ट जारी किया। यह रिपोर्ट तिब्बत में शांतिपूर्ण विरोध के समय हुई गतिविधियों के बारे में पूरा ब्यौरा और गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कमीशन के 2009 के सालाना रिपोर्ट को तैयार करने में भी इस रिपोर्ट की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2008 में तिब्बत के लोगों ने चीन के द्वारा थोपी जा रही सरकारी नीति और कानूनों के खिलाफ अपनी भावना अभिव्यक्त की। उसमें तिब्बतियों ने साफ जाहिर किया था कि चीन के द्वारा थोपे जा रहे नीति और कानून तिब्बतियों के सांस्कृतिक पहचान और विरासत के लिए नुकसानदायक हैं।

भारत में पढ़े तिब्बती व्यापारी दोरजी टाशी जेल में हैं

(फायूल डॉट कॉम, 19 अगस्त, धर्मशाला)

किसी भी राजनीतिक मसले पर चीन का दमनकारी रवैया कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन प्रभावशाली तिब्बतियों पर टूट पड़ने की घटनाओं ने

जिसमें दो प्रख्यात कारोबारियों को जेल भेजने की घटना भी शामिल है, तिब्बत के प्रेक्षकों के लिए चीन के इरादे पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। एक एंटीक डीलर कर्मा सामदुप के जेल जाने के बाद अब होटल चेन और रियल एस्टेट कारोबार में लगे तिब्बती कारोबारी हस्ती दोरजी टाशी के भी जेल में बंद रहने की खबर मिल रही है। इन दोनों व्यापारियों को पहले चीन सरकार सम्मानित कर चुकी है। पर्यावरणविद और समाजसेवी कर्मा सामदुप के बाद दोरजी टाशी ऐसे दूसरे प्रमुख तिब्बती नागरिक हैं जिन्हें चीन सरकार ने निशाना बनाया है। इन दोनों हस्तियों ने राजनीति से दूरी बनाए रखा है और समझा जाता है कि चीनी व्यवस्था की हदों में रहकर ही काम करते रहे हैं। दोरजी के शहर आमदो में लाबरांग काउंटी के ही मूल निवासी जामयांग ल्हामों ने बताया, "तिब्बतियों, चीनियों और विदेशी पर्यटकों के बीच वह 'याक ताशी' के नाम से मशहूर रहे हैं। अपनी तिब्बती पहचान के प्रति मजबूती से सजग रहते हुए इतने सफल कारोबारी बनने के लिए तिब्बती उन पर गर्व करते हैं।" करीब 45 करोड़ पाउंड की संपत्ति रखने वाले शीर्ष तिब्बती व्यापारी दोरजी टाशी को साल 2008 में ल्हासा में हुए विद्रोह के सिलसिल में गिरफ्तार किया गया है। यह विद्रोह उस साल मार्च में ल्हासा के साथ तिब्बत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। 37 साल के युवा व्यापारी को मार्च, 2008 में ही हिरासत में लिया गया है और तबसे उनसे किसी का संपर्क नहीं हो पाया है। 26 जून, 2010 को ल्हासा के नगर निगम माध्यमिक जन न्यायालय ने तीन दिन तक चले एक गुप्त मुकदमे में 'गैरकानूनी कारोबार करने' के लिए दोरजी टाशी को दोषी ठहराया। जबकि दोरजी टाशी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और उन्हें चीन सरकार से ही कई तरह का सम्मान मिल चुका है। इनमें तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 'बेहतरीन निजी कारोबार अवॉर्ड', शिगास्ते प्रशासन द्वारा 'गरीबी हटाने में विशेष योगदान के लिए अवॉर्ड और गांसू की प्रांतीय समिति और सरकार द्वारा 'सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए गन्नान अवार्ड' शामिल है। शिगास्ते की कम्युनिस्ट यूथ लीग कमेटी द्वारा हर दस साल पर 'यूथ सिविलाइजेशन इंडिविजुल एचीवमेंट अवॉर्ड' दिया जाता है और दोरजी को साल 2005 में यह सम्मान मिल चुका है। इस अवॉर्ड को पाने में उनके 'तिब्बत मानसरोवर ग्रुप' द्वारा किए जा रहे कार्यों का योगदान है जिसमें लक्जरी होटल, ट्रैवल एजेंसियां और रियल एस्टेट कारोबार शामिल हैं।

जामयांग ने बताया, 'दोरजी टाशी लांबरांग मठ से करीब 3 किलोमीटर दूर सा–कार क्षेत्र में रहने वाले एक विनम्र परिवार से हैं।" दोरजी टाशी ने धर्मशाला के निकट सुजा में स्थित टिबेटन चिल्ड्रेंस विलेज स्कूल से पढ़ाई की है। भारत में अध्ययन करने के बाद वह तिब्बत लौट गए और राजधानी ल्हासा में याक होटल की शुरुआत की और यह काफी सफल साबित हुआ। इसके बाद उनके अन्य कारोबारी उद्यम भी काफी सफल रहे। जामयांग ने फुयाल को बताया, 'ल्हासा में ज्यादातर टांसपोर्ट कारोबार और टेवल एजेंसियां दोरजी द्वारा ही संचालित हो रही हैं और मैं यह कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में करीब 80 फीसदी पर्यटन में उनका योगदान है।

जब हमने पूछा कि क्या दोरजी किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि या 'अलगाववादी' गतिविधि में शामिल हो सकते हैं जैसा कि चीन सरकार का आरोप है तो जामयांग ने कहा, "वह इतने मूर्ख नहीं हैं कि इस बात को न समझ पाएं कि तिब्बत के भीतर रहकर किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने का क्या परिणाम हो सकता है।"

दोरजी को जेल में बंद करने के कुछ महीनों बाद उनके बड़े भाई को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा दे दी गई। जामयांग ने बताया कि टाशी के चचेरे भाई डुकर टाशी को भी 5 साल कैद की सजा दी गई है। साल 2005 में दोरजी टाशी ने चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात की थी। जामयांग ने कहा, "मैंने सुना है कि दोरजी को स्थानीय चीनी सुरक्षा बल के जवानों ने नहीं, बल्कि बीजिंग से आई सादे कपड़ों वाली पुलिस ने गांसू प्रांत की राजधानी लांझू से गिरफ्तार किया है।"

यह कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्वासित तिब्बती गैर सरकारी संस्थाओं और दलाई लामा को चंदा देने के आरोप में दोरजी ताशी को गिरफ्तार किया गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के तिब्बती विद्वान रॉबी बर्नेट ने बताया, "तिब्बती निर्वासित समुदाय पश्चिमी देशों में रहने वाले तिब्बती लोगों से ही चंदा लेता है न कि चीन के भीतर के लोगों से। उनसे इस तरह के जोखिम लेने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।" जामयांग ने कहा, 'टाशी ऐसे तिब्बती हैं जिनको तिब्बती होने पर गर्व है और उन्होंने एक ऐसी जमीन पर तिब्बती पहचान एवं गौरव को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है जहां अब हान चीनी बाशिंदों की बहुतायत हो गई है। हो सकता है कि इतना ज्यादा सफल हो जाने

कोलंबिया विश्वविद्यालय के तिब्बती विद्वान रॉबी बर्नेट ने बताया तिब्बती निर्वासित समुदाय पश्चिमी देशों में रहने वाले तिब्बती लोगों से ही चंदा लेता है न कि चीन के भीतर के लोगों से। उनसे इस तरह के जोखिम लेने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।" जामयांग ने कहा, 'टाशी ऐसे तिब्बती हैं जिनको तिब्बती होने पर गर्व है और उन्होंने एक ऐसी जमीन पर तिब्बती पहचान एवं गौरव को बनाए रखने के लिए प्रयास किया है जहां अब हान चीनी बाशिंदों की बहुतायत हो गई है।

की वजह से उन्हें चीनी अधिकारी पसंद न करते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया है।

पुलिस फायरिंग में 3 तिब्बती मरे, 30 घायल

(फायूल, 24 अगस्त, धर्मशाला)

तिब्बत के सिचुआन प्रांत के पालिउल काउंटी में गत 18 अगस्त को एक सरकारी इमारत के बाहर अपनी शिकायत लेकर जमा हुए निहत्थे तिब्बती नागरिकों पर चीनी सुरक्षा बलों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जिससे तीन तिब्बती नागरिक मारे गए और 30 घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि यह घटना पालीउल काउंटी के शारचू गेशोड गांव की है जिसके नेता ताशी सांगपो ने स्थानीय चीनी अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की थी कि क्षेत्र में सोना के खनन की गतिविधियां रोकी जाएं। सांगपो ने चीन सरकार के सोना खनन गतिविधि पर आपत्ति करते हुए क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई थी।

नेपाल की नीति में आए इस बदलाव से निर्वासित तिब्बती सरकार चिंतित हो गई है।केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले 2003 में नेपाल आने वाले 18 तिब्बतियों को पकड़कर चीनी अधिकारियों के हवाले किया गया था।

स्थानीय तिब्बती नागरिकों को चिंता है कि इस खनन का असर उनके जन–जीवन पर पड़ेगा और वे सरकार से लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गांव के करीब 100 तिब्बती नागरिक सरकारी कार्यालय के बाहर अपनी मांग को लेकर जमा हुए थे। 18 अगस्त की रात को सबसे पहले चीनी सुरक्षा बलों ने हानिकारक गैस छोड़कर तिब्बतियों को बेहोश करने का प्रयास किया। चीनी सुरक्षा बल बेहोश तिब्बती नागरिकों को लेकर एक ट्रक की तरफ जाने लगे जिसे देखकर ताशी सांगपो और कई लोग उनसे भिड़ गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें तीन तिब्बती नागरिक मारे गए। इनमें ताशी सांगपो के दो रिश्तेदार सोएसो और पापहो भी शामिल थे। करीब 30 तिब्बती नागरिक गोली लगने से घायल हो गए हैं और कई अन्य को हिरासत में ले लिया गया है। घायल तिब्बती या गिरफ्तार लोग कैसे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के काउंटी से भी सुरक्षा बलों को बुलाया गया है।

नेपाल के चीन से बढ़ते संबंध से तिब्बत चिंतित

(हिंदुस्तान टाइम्स, धर्मशाला, 18 अगस्त)

नेपाल के चीन से बढ़ते संबंधों और वहां रह रहे तिब्बतियों के प्रति बदलती नीति ने दलाई लामा की निर्वासित तिब्बती सरकार को चिंता में डाल दिया है। निर्वासित सरकार के कैबिनेट सचिव मिग्युल दोरजी ने कहा कि नेपाल में जो स्थिति है उसे वहां रह रहे तिब्बती चिंतित हैं। तिब्बत सरकार के अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में पांच अलग–अलग जगहों पर कुल 15,000 तिब्बती रह रहे हैं। चीन के कब्जे वाले तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र यानी टीएआर से नेपाल की सीमा पर कर नेपाल आने वाले तिब्बतियों को पकड़ कर नेपाली सरकार तिब्बती अधिकारियों के हवाले कर देती है। हाल ही में दम शहर के पास सीमा पार कर आने वाले तीन तिब्बतियों को पकड़कर नेपाल सरकार ने चीनी अधिकारियों के हवाले किया। उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और बाद में चीनी इमिग्रेशन अधिकारी के हवाले कर दिया गया। इनमें दो की पहचान भिक्षु दावा (20) और दोरजी (21) के रूप में की गई, तीसरी महिला की पहचान 22 वर्षीय पेंपा के रूप में हुई। निर्वासित सरकार के मुख्यालय से मिली अपुष्ट खबर के मुताबिक तीनों को हेलीकॉप्टर से चीनी सीमा में वापस भेज दिया गया।

उधर वाशिंगटन में तिब्बतियों के मुद्दे पर काम करने वाली संस्था इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टिबेट ने कहा कि तिब्बत वापस जाने वाले तीनों तिब्बतियों को जेल में डाल दिया गया। नेपाल की नीति में आए इस बदलाव से निर्वासित तिब्बती सरकार चिंतित हो गई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले 2003 में नेपाल आने वाले 18 तिब्बतियों को पकड़कर चीनी अधिकारियों के हवाले किया गया था।

इसके पहले माओवादी गठबंधन सरकार के दिनों में नेपाल ने तिब्बती प्रशासन द्वारा वहां तिब्बती शरणार्थियों के लिए खोले गए स्वागत केंद्र को बंद कर दिया था। तिब्बती सरकार के अधिकारियों ने बताया कि चीन में ओलंपिक के पहले तिब्बतियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किये जाने के बाद नेपाली सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई। इन प्रदर्शनों में कई तिब्बतियों की मृत्यु हो गई। मरने वालों की संख्या को लेकर हालांकि चीन सरकार और निर्वासित तिब्बती सरकार के आंकड़ों में काफी अंतर है। चीन सरकार का कहना है कि करीब 200 तिब्बती मरे थे, जबकि तिब्बती सरकार का कहना है कि मरने वालों की संख्या अधिक है और करीब 1000 लोग घायल भी हुए थे।

2008 में प्रदर्शन के बाद तिब्बत से भाग कर भारत आने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। ओलंपिक के पहले हुए इस प्रदर्शन से पहले हर साल करीब 2000 से 3000 तिब्बती भाग कर भारत पढ़ने के लिए आते थे। तिब्बती स्वागत केंद्र के निदेशक नगवांग

नोर्बू ने मैकलोडगंज में कहा कि चीनी सरकार के खौफ के कारण तिब्बत से भागने वालों की संख्या घट गई है। इस साल फरवरी से अब तक सिर्फ 700 तिब्बती ही भाग कर धर्मशाला आए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तिब्बत से भागने वालों की संख्या में और कमी आ सकती है। क्योंकि नेपाल और चीन के सीमा सुरक्षा बल में चीनी विरोध को दबाने के लिए समझौता हुआ है। ल्हासा से 1959 में भारत आए तिब्बती आध्यात्मिक गुरु ने निर्वासित तिब्बतियों की शिक्षा के लिए अनेक अच्छे स्कूल खोले हैं। ये स्कूल भी तिब्बतियों के चीनी कब्जे वाले तिब्बत से भाग कर आने का एक प्रमुख कारण हैं।

सबसे बड़ा कैलीग्राफी स्क्रॉल– तिब्बतियों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

(वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी डॉट ऑर्ग, 5 अगस्त न्यूयार्क सिटी, यूएसए)

जमयांग दोरजी चक्रीशर ने 163.2 मीटर लंबा कैलीग्राफी स्क्रॉल बनाकर दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी स्क्रॉल बनाने का विश्व रिकार्ड बनाया है। 56 साल के मास्टर कैलीग्राफर जमयांग दोरजी भारत के सिक्किम में रहते हैं। दुनिया के इस सबसे लंबे कैलीग्राफी स्क्रॉल में चौदहवें दलाई लामा के लिए तैयार की गई प्रार्थना लिखी गई है। इन प्रार्थनाओं को 32 तिब्बती आध्यात्मिक गुरुओं ने तैयार किया है। यह स्क्रॉल लोक्ता तिब्बती हस्त निर्मित कागज पर तैयार की गई है जिसे नेपाल में काम कर रही एक तिब्बती कंपनी ने तैयार किया है। इस स्क्रॉल को जापानी सुमि इंक से लिखा गया है।

इस स्क्रॉल का प्रदर्शन तेंजिन ग्यात्सो इंस्टीट्यूट में अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर लेखक सोग्यल रिनपोछे और दलाई लामा के प्रतिनिधि लोदी ग्यारी रिनपोछे की मौजूदगी में प्रदर्शित किया गया।

जमयांग को इस कैलीग्राफी को तैयार करने में 6 महीने लगे हैं। इसमें 65,000 तिब्बती अक्षरों का उपयोग हुआ है। इसे तिब्बत की अलग अलग कैलीग्राफी स्टाइल जैसे सुगरिंग, सुगथंग, सुगमा क्युग और उमेद का क्युग फॉर्म में लिखा गया है।

जमयांग का जन्म तिब्बत के ल्हासा में हुआ था। उन्होंने भारत के शिमला और मसूरी के तिब्बत शरणार्थी शिविरों में चलने वाले स्कूलों में पढ़ाई की है। उन्होंने सिक्किम सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवा की है। बाद में वे भारत के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार के सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ गए। जमयांग फिलहाल नेपाल में रह रहे हैं और कंजर्वेंसी फॉर टिबेटन आर्ट्स एंड कल्चर (सीटीएसी) के रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं।

ब्यालाकुप्पी में पहले तिब्बती राष्ट्रीय आमसभा का आयोजन

(टिबेट डॉट नेट, 27 अगस्त, धर्मशाला)

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के ब्यालाकुप्पी स्थित तिब्बती बस्ती में करीब 450 तिब्बती प्रतिनिधि यहां गुरुवार को शुरू हुए पहले राष्ट्रीय आमसभा में शरीक होने के लिए जुटे हैं। इन प्रतिनिधियों में निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य, कशग यानी तिब्बती मंत्रिमंडल के सदस्य, तिब्बती बौद्ध और बॉन संप्रदाय के चार स्कूलों के प्रतिनिधि, स्थानीय तिब्बती विधानसभाओं के प्रतिनिधि, आम जनता, बॉड–रंगवांग देनपाई लेगुल सॉकछुंग, एनजीओ, स्कूलों से जुड़े प्रतिनिधि, डॉक्टर, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इस आमसभा के छठें दिन सभी प्रतिनिधि कई व्यापक मसलों पर बात करेंगे जैसे राजनीतिक मामले, लोकतंत्र को बढ़ावा देने, धर्म, संस्कृति, बस्तियों के लिए व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, विभिन्न समुदायों के बीच बिखरे हुए तिब्बतियों का कल्याण और तिब्बत मसले का हल मध्यम मार्ग नीति से निकालने की बात शामिल हैं।

इन सभी मसलों पर बात करने के लिए प्रतिनिधियों को 8 उपसमितियों में बांटा गया है। इस महासभा में अपने उद्घाटन भाषण में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेनपा शेरिंग ने कहा, "सभी प्रतिनिधियों को अपने स्वभाव, रुचि और जिम्मेदारी के हिसाब से इस बैठक की उपसमिति का चुनाव करने का विकल्प दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि वे इस बैठक को सार्थक बनाने के लिए अपने पूरे कौशल और बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम इस्तेमाल करेंगे।" अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे विभिन्न मसलों पर अपनी जानकारी के आधार पर कुछ सुझाव दें।

अपने संबोधन में कालोन ट्रिपा सैमदोंग रिनपोछे जी ने कहा, "दूसरे शरणार्थी समुदायों के विपरीत निर्वासित तिब्बती समुदाय अगर समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे अनुकरणीय और सफल समुदाय साबित हुआ है। लेकिन निर्वासित तिब्बतियों की मौजूदा स्थिति को आगे बनाए रखना पूरी तरह तिब्बती लोगों की सामूहिक योग्यता और उनकी सोच एवं नैतिक आचरण पर निर्भर करेगा।" कालोन ट्रिपा ने कहा कि निर्वासित तिब्बती समुदाय

जमयांग को इस कैलीग्राफी को तैयार करने में 6 महीने लगे हैं। इसमें 65,000 तिब्बती अक्षरों का उपयोग हुआ है। इसे तिब्बत की अलग अलग कैलीग्राफी स्टाइल जैसे सुगरिंग,सुगथंग, सुगमा क्युग और उमेद का क्युग फॉर्म में लिखा गया है।जमयांग का जन्म तिब्बत के ल्हासा में हुआ था। उन्होंने भारत के शिमला और मसूरी के तिब्बत शरणार्थी शिविरों में चलने वाले स्कूलों में पढ़ाई की है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ये असामान्य बाढ़ हैं और रूस में फैली विकराल आग के पीछे एक बड़ी समस्या है, जिसकी जड़ ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों में छुपी है।

ने 1959 में निवार्सन की समस्या से 70 के दशक तक कई तरह की समस्याओं से जूझने के बाद जीविका और सामाजिक स्थिरता के मामले में काफी हद तक स्थायित्व हासिल कर लिया है। लेकिन 1980 के बाद से और खासकर पिछले दो दशकों में इस सकारात्मक रुख में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। बैठक के दौरान इन बदलावों का आकलन किया जाना चाहिए और उन पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इन मसलों को ठीक से संभाला नहीं गया तो समूचे तिब्बती नागरिकों और खासकर निर्वासित तिब्बतियों की नियति पर गंभीर असर पड़ेगा।

कालोन ट्रिपा ने शिक्षा में स्पेशलाइजेशन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर समुदाय बनाने और नैतिक आचरण के क्षरण को रोकने के लिए मजबूत प्रयास करने के लिए गंभीर विचार–विमर्श करने पर जोर दिया। इस बैठक की अंतिम संस्तुतियों को 31 अगस्त को समापन समारोह के दिन परम पावन दलाई लामा की उपस्थिति में पेश किया जाएगा।

बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए दलाई लामा ने प्रार्थना की

"मेरा खून तिब्बत की आज़ादी के लिए समर्पित है, तिब्बत की आज़ादी के लिए समर्थन देना महत्वपूर्ण है। मैं इस संदेश के साथ पूरी दुनिया से आह्वान करने जा रहा हूं। मैंने अपने खून से बराक ओबामा का पोर्ट्रेट बनाया है।

(टिबेट डॉट नेट, 14 अगस्त, धर्मशाला)

परमपावन दलाई लामा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में बाढ़ के कारण मरने वाले कई लोगों और संपत्ति को हुए नुकसान के कारण मुझे गहरा दुःख हुआ है। मैंने उनके लिए प्रार्थना की है और संकेत के रूप में राहत और बचाव कार्य में कुछ दान भी किया है।

उधर तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के गांसू प्रांत के कान्लो के दक्षिण–पूर्व में द्रुगचू में हुए भूस्खलन के कारण हुए भारी तबाही से भी मुझे बहुत दुःख हुआ है। इसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। बताया गया है कि यह पिछले करीब एक दशक की सबसे भीषण दुर्घटना है। दलाई लामा ने कहा, "मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने राहत और बचाव कार्य के लिए वहां का दौरा किया होगा। मैं इस प्राकृतिक विभीषिका में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों और किसी भी रूप में प्रभावित हुए लोगों के साथ पूरे दिल से सहानुभूति जताता हूं।"

विशेषज्ञों का कहना है कि ये असामान्य बाढ़ हैं और रूस में फैली विकराल आग के पीछे एक बड़ी समस्या है, जिसकी जड़ ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों में छुपी है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपनी सम्मिलित विरासत इस नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। इस प्रार्थना सभा में मैं इन विभीषिका में मारे गए और प्रभावित हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैकलोडगंज के प्रमुख मंदिर (सुगलागखांग) में भी एक प्रार्थना सभा में शामिल हुआ।

तिब्बत आंदोलन के लिए हस्ताक्षर अभियान में भाामिल हुईं मिस तिब्बत

(एएनआई, 14 अगस्त, धर्मशाला)

मिस तिब्बत, 2010 तेनजिन नॉरजोम तिब्बत में चीनी दमन के खिलाफ शुक्रवार को धर्मशाला में तिब्बती आंदोलनकारियों के साथ एक हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुईं। इस अभियान के तहत तिब्बती आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों का हस्ताक्षर एक बड़े बैनर पर लिया गया। बाद में यह बैनर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजा जाएगा।

नॉरजोम ने कहा, "सबसे पहले मिस तिब्बत के रूप में मेरा तिब्बती आंदोलन के लिए फर्ज बनता है। मैंने देखा कि एक गैर तिब्बती व्यक्ति तिब्बत की आज़ादी के लिए अपना खून दे रहा है, इससे मुझे वास्तव में प्रेरणा मिली है। जब मुझे मिस तिब्बत का ताज मिला उसके बाद यह जानकारी हुई। इससे वास्तव में मैं प्रेरित हुई। मुझे लगा कि मुझे भी तिब्बत के लिए कुछ करना चाहिए।" गौरतलब है कि एक भारतीय कार्यकर्ता डॉ. महेश यादव हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं और वह पिछले 14 साल से अपने खून से विभिन्न वैश्विक नेताओं का पोर्ट्रेट बनाते रहे हैं। यादव ने तिब्बत की आज़ादी का आह्वान करते हुए अमेरिकी राष्टपति बराक ओबामा का पोर्ट्रेट बनाया है। यादव ने कहा, "मेरा खून तिब्बत की आज़ादी के लिए समर्पित है, तिब्बत की आज़ादी के लिए समर्थन देना महत्वपूर्ण है। मैं इस संदेश के साथ पूरी दुनिया से आह्वान करने जा रहा हूं। मैंने अपने खून से बराक ओबामा का पोर्ट्रेट बनाया है। यह मानवता को बचाने का एक संदेश है। हमने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से तिब्बत को बचाने के लिए इसलिए आह्वान किया है क्योंकि दलाई लामा अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं।"

दूसरी तरफ तिब्बती स्वयंसेवकों के एक समूह ने निर्वासित तिब्बती सरकार के कालोन ट्रिपा (प्रधानमंत्री) के लिए आने वाले चुनाव के लिए एक उम्मीदवार लोबसांग सिंगे का प्रचार अभियान शुरू करने के लिए एक वेबसाइट शुरू किया है।

लोबसांग वांग्याल ने बताया, 'हमने हाल में एक वेबसाइट कालोनट्रिपा डॉट ओआरजी की शुरुआत की है और यह डॉ. लोबसांग सिंगे के प्रचार के लिए है। सिंगे ने हार्वर्ड से लॉ स्नातक की पढ़ाई की है और फिलहाल वह हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे हैं। बहुत से निर्वासित तिब्बती युवा उन्हें निर्वासित सरकार के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1959 में चीन शासन के खिलाफ तिब्बतियों की क्रांति के बाद दलाई लामा के साथ करीब 80,000 तिब्बती भारत आ गए थे और इसके बाद अब तक इनकी आबादी और बढ़ती गई है।

सिंगे ने हार्वर्ड से लॉ स्नातक की पढ़ाई की है और फिलहाल वह हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे हैं। बहुत से निर्वासित तिब्बती युवा उन्हें निर्वासित सरकार के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1959 में चीन शासन के खिलाफ तिब्बतियों की क्रांति के बाद दलाई लामा के साथ करीब 80,000 तिब्बती भारत आ गए थे और इसके बाद अब तक इनकी आबादी और बढ़ती गई है।

चीनी नेताओं को निर्भीक दृष्टि और तिब्बत मसले को हल करने का साहस दिखाना चाहिए

लोदी ग्यालत्सेन ग्यारी

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में परमपावन दलाई के विशेष दूत कसुर लोदी ग्यालत्सेन ग्यारी ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा चीनी नेतृत्व इस अवसर का फायदा उठाते हुए सामयिक तिब्बत के कठिन सचाई का सामना करने का साहस दिखाएगा और उसी तरह की निर्भीक दृष्टि का प्रदर्शन कर पाएगा जैसा कि देंग जियोपिंग और हू याओबांग ने दिखाया था। लोदी ग्यारी ने लिखा है–

मैंने पिछले तीन दशक का ज्यादातर समय चीनी नेताओं से वार्ता में परमपावन दलाई लामा का प्रतिनिधित्व करने में बिताया है। मैं अपनी पूरी ताकत इस बात में लगाई है कि चीनी नेतृत्व तिब्बती जनता की आकांक्षा और परमपावन दलाई लामा के दृष्टिकोण को समझ सके ताकि शांति और मेलमिलाप का कोई साझा मार्ग तलाशा जा सके।

इन वर्षों में मैंने चीनी नेतृत्व की प्रकृति और ढांचे में भारी बदलाव देखा है–देंग जियोपिंग के निर्भीकता प्रदर्शन के युग से हू याओबांग जैसे राजनेता के व्यापक दृष्टिकोण तक, हाल के दिनों में संस्थागत दबावों और दृढ़ता की कमी के युग तक। जब भी कोई स्वप्नद्रष्टा नेतृत्व आता है तो हम यह देख सकते हैं कि चीन ऐसे कदम उठाने में सक्षम होता है जिससे देश के एकता और अखंडता की रक्षा होती है, सभी नागरिकों के हितों को बढ़ावा मिलता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की सकारात्मक छवि बनती है। तिब्बत मसले पर चीनी नेतृत्व का जिस तरह का रवैया रहा है उसका असर चीन में सद्भावपूर्ण समाज बनाने और विश्व मंच पर उसकी छवि पर पड़ रहा है।

अपने काम के एक हिस्से के तहत ही मैं यह समझने का प्रयास करता रहा हूं कि आखिर चीनी नेतृत्व के मौजूदा रवैए के पीछे क्या कारण हो सकता है। मुझे लगा कि इसके पीछे तीन तरह की सोच हो सकती है। पहली सोच यह हो सकती है कि चीन आगे बढ़ रहा है और उसकी इस नई पहचान में समाहित होने के लिए सभी जातीय समूहों को अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं में परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसा लगता है कि चीन में इस दृष्टिकोण को मानने वाले तिब्बती लोगों की अलग पहचान का सम्मान नहीं करना चाहते और उसे दबाना चाहते हैं। बीजिंग को यह गलतफहमी हो गई है कि तिब्बत में उसने जो कृत्रिम स्थिरता ला रखी है वह इस बात का संकेत है कि तिब्बतियों में उसकी नीति को लेकर मौन समर्थन है। लेकिन इसे संतोष या सहमति मान लेना ठीक नहीं है। इसकी जगह यह मौन रूप से कड़वाहट और निराशा बढ़ने का संकेत है। दमनकारी दशाओं में इस तरह का माहौल और बढ़ता है। साफ कहा जाए तो यह ऐसी चुप्पी है जिसमें भविष्य में हिंसा और अस्थिरता के बीज देखे जा सकते हैं। दूसरे तरह की सोच यह है कि यदि चीन सरकार तिब्बती क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने में सफल होती है, तिब्बती लोगों की चिंताओं का समाधान होता है तो समूचा मसला अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यह भी तिब्बती समस्या को हल करने का काफी संकुचित रवैया है। तिब्बती लोगों का आर्थिक रूप से हाशिए पर जाना एक ऐसी सचाई है जिसका चीनी नेतृत्व को समाधान करना है, आधिकारिक आंकड़ों से साफ है कि तिब्बती लोग आर्थिक विकास के पैमाने के बिल्कुल निचले पैमाने पर हैं।

हालांकि, जैसा कि तिब्बत मसले के चीनी विद्वान और विशेषज्ञ यह जानते हैं कि तिब्बती लोग अपने विशिष्ट संस्कृति के प्रति भारी सम्मान रखते हैं, जिसने नए चीन के विकास में भारी योगदान दिया है।

तिब्बती लोगों को इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फलने–फूलने तथा इसको और समृद्ध बनाने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। यह केवल आर्थिक विकास से नहीं हो सकता, हालांकि यदि अच्छी मंशा से किया जाए तो कुछ जरूर हो सकता

है। उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का प्रदर्शन किए बिना यदि कोई आर्थिक एकीकरण प्रयास किया गया तो वह तिब्बती लोगों में और असंतोष को ही बढ़ावा देगा। समूचे तिब्बती क्षेत्रों में साल 2008 से ही जिस तरह प्रदर्शन हुए उससे चीनी अधिकारियों को यह साफ संदेश समझ जाना चाहिए था।

तीसरी सोच यह है कि चीन को मौजूदा दलाई लामा के निधन का इंतजार करना चाहिए क्योंकि इसके बाद तिब्बत मसला अपने आप खत्म हो जाएगा। यह सोच इस धारणा पर आधारित है कि एक नेतृत्वविहीन और भ्रांतिपूर्ण आंदोलन टुकड़ों में बंट जाएगा और अंततः वह अप्रासंगिक हो जाएगा। कई वजहों से यह सोच काफी गलत है और यह चीन के अपने भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वे यह नहीं समझते कि आज किसी आंदोलन के टुकड़ों में बंटे होने का मतलब उसका अप्रासंगिक हो जाना नहीं होता है। बल्कि इसका मतलब अकल्पनीय क्रांतिकारिता और बहुत ज्यादा जोखिम होता है। धुंधला होने की जगह तिब्बती राजनीतिक आंदोलन मौजूदा 14वें दलाई लामा के नए रहने पर अपने को नए सिरे से तलाश करेगा और ऐसा आंदोलन बनेगा जो जटिल और अप्रबंधनीय नहीं रहेगा। यह देखकर काफी तकलीफ होती है कि चीन के नेता शुरुआती दिनों के साहसी सुधार प्रक्रिया से अब कितने दूर हो गए हैं। अस्सी के दशक के शुरुआती सालों में मैं जिन नेताओं को जानता था उनका उन कठिन बदलावों के प्रति दृढ़ विश्वास था जिसकी माओ के बाद वाले चीन को जरूरत थी। हू याओबांग जैसे नेता यह समझते थे कि चीन के भविष्य की महानता असल स्थिरता के लिए जरूरी जमीनी काम शुरू करने के लिए उसके नेताओं के जिम्मेदाराना कार्यों से ही होगी। हू ने तिब्बत से संबंधित कई साहसी नीतियों के लिए आह्वान किया था। वह खुले दिल के एवं ईमानदार थे, कुछ करने का, सचाई का सामना करने का और जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस रखते थे, इसलिए वह तिब्बती लोगों को दिल जीत सके थे।

मुझे उम्मीद है कि आज के चीन के नेता अवसर का फायदा उठाएंगे और सामयिक तिब्बत के कठिन सचाई का सामना करने का साहस दिखाएंगे, जैसी साहसी दृष्टि देंग और हू द्वारा दिखाई गई थी।

जहां तक हमारी बात है, अपनी तरफ से हमने औपचारिक रूप से तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता के लिए दिए उस ज्ञापन में परमपावन के रुख को साफ कर दिया है जो नवंबर, 2008 में आठवें दौर की वार्ता में पेश किया गया था।

इस साल जनवरी में पेश किए गए ज्ञापन और संबंधित नोट के द्वारा हमने यह साफ और निश्चित शर्तों में कहा है कि हम चीन जनवादी गणराज्य, उसके संविधान और कानून के ढांचे के तहत केवल वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं। हमने यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि हम चीन जनवादी गणराज्य की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता, केंद्र सरकार की सत्ता का सम्मान करेंगे और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्वायत्तता की व्यवस्था का पालन करेंगे। लेकिन चीन की केंद्र सरकार को भी हमारे विशिष्ट और अलग पहचान को बनाए रखने के लिए तिब्बती जनता के वैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह हमारी प्रमुख चिंता है। चीनी नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तिब्बत मसले का वास्तविक हल निकालने के लिए गंभीर प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। मौजूदा समय में जो विशिष्ट अवसर मिलता दिख रहा है उसकी वजह से इस जिम्मेदारी की तात्कालिकता और सुस्पष्ट हो गई है। इसके पहले दलाई लामा जैसा कोई तिब्बती नेता नहीं था जो तिब्बती एवं चीनी जनता के लिए स्वप्नदर्शी बदलाव लाने हेतु मजबूती से और लगातार ऐसे चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण रास्त पर चलन जारी रखे।

चीन जनवादी गणराज्य अपने को एक बहुजातीय राज्य बताता है जिसमें सभी राष्ट्रीयता के लोग बराबर की ताकत और अधिकार रखते हैं। उसका दावा है कि यह ऐसा देश नहीं है जहां बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों पर राजनीतिक प्रभुत्व रखते हों। चीनी नेताओं को एक ऐतिहासिक विकल्प चुनना होगाः क्या वे चीन को ऐसे शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जाएंगे जिसमें तिब्बती लोगों को अंततः एक आधुनिक चीनी राज्य के भीतर एक टिकाऊ घर मिल सके? या वे दूसरे तरह का भविष्य देखना चाहेंगे क्योंकि अलगाववाद के बीज दिख चुके हैं जिसमें अलग तरह के भविष्य के लिए नकारात्मक परिणाम हासिल होंगे?

मैं जानता हूं कि परमपावन दलाई लामा ने इतिहास का सही पक्ष चुना है। मैं केवल इस बात की उम्मीद कर सकता हूं कि चीनी नेता भी इसके लिए तैयार दिखें।

(लोदी ग्यारी परमपावन दलाई लामा के विशेष दूत और चीनी नेतृत्व के साथ वार्ता करने वाले दल के मुखिया हैं)

चीनी नेताओं को एक ऐतिहासिक विकल्प चुनना होगाः क्या वे चीन को ऐसे शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जाएंगे जिसमें तिब्बती लोगों को अंततः एक आधुनिक चीनी राज्य के भीतर एक टिकाऊ घर मिल सके? या वे दूसरे तरह का भविष्य देखना चाहेंगे क्योंकि अलगाववाद के बीज दिख चुके हैं जिसमें अलग तरह के भविष्य के लिए नकारात्मक परिणाम हासिल होंगे?